वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर एवं अन्य

बनाम

इज़हार हुसैन

10 अगस्त, 1989

[रंगनाथ मिश्रा और कुलदिप सिंह, जेजे.]

प्रशासनिक कानूनः सांविधिक नियम-कार्यकारी निर्देशों द्वारा संशोधित या संशोधित नहीं किया जा सकता है संवैधानिक रूप से अमान्य नियम को कार्यकारी निर्देशों द्वारा मान्य नहीं किया जा सकता है-निर्देश केवल नियम का स्थान ले सकते हैं और नियम का स्थान नहीं ले सकते हैं।

मौलिक नियमः नियम 56 जे-समय पूर्व सेवानिवृत्ति-केवल 'जनहित' में।

उदारीकृत पेंशन नियम, 1960: नियम 2 (2)-अनिवार्य सेवानिवृत्ति-30 साल की योग्यता सेवा के बाद 'विवेकाधिकार' पर अनुमत सरकार-कोई गाइड लाइन प्रदान नहीं की गई-नियम अमान्य है।

प्रत्यर्थी, और डाक और टेलीग्राफ विभाग में कर्मचारी, लिबेरा लाइसड पेंशन नियम, 1950 के नियम 2 (2) के तहत सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे, जो सरकार को 30 साल की योग्यता सेवा पूरी करने के बाद किसी भी समय एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का अधिकार देता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थी की रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मानते हुए खारिज कर दिया कि नियम में कोई कमजोरी नहीं है। हालांकि, डिवीजन बेंच ने स्वीकार किया कि प्रत्यर्थी द्वारा दायर विशेष अपील और नियम 2 (2) को अमान्य घोषित किया गया।

इस न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि भारत सरकार ने 11 जुलाई, 1955 को निर्देश जारी किए थे और 8 फरवरी, 1956 में

यह निर्धारित किया गया कि पेंशन नियमों के नियम 2 (2) के तहत सेवानिवृत्ति तब प्रभावी होनी चाहिए जब ऐसी सेवानिवृत्ति जनहित में आवश्यक हो। यह भी तर्क दिया गया कि गृह मंत्रालय का 30 नवंबर, 1962 का ज्ञापन, जो भारत के राष्ट्रपति के नाम से जारी किया गया था, वैधानिक था और इसका पेंशन नियमों के नियम 2 (2) में संशोधन करने का प्रभाव था, और नियम और ज्ञापन को एक साथ पढ़कर नियम 2 (2) के तहत शक्ति का उपयोग केवल अनुपयुक्त कर्मचारियों को हटाने के लिए किया जा सकता था।

अपील को खारिज करते हुए, यह न्यायालय, अभिनिर्धारित किया कि :

(1) केंद्र सरकार के कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। सरकार के पास नियम 56 (जे) के तहत पूर्ण अधिकार है। 'पब्लिक इन' में एक कर्मचारी को समय से पहले सेवानिवृत्त करने के लिए मौलिक नियम 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 'टेरेस्ट'। सरकार ने उदारीकृत पेंशन नियमों के नियम 2(2) के तहत भी सेवानिवृत्त होने की शक्ति योग्यता के 30 वर्ष पूरे करने के बाद किसी भी समय एक नौकर सेवा करते हैं। [798 एच-799 ए]

(2) मौलिक नियम 56 (जे) को पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए सरकार का प्रावधान है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल सार्वजनिक रूप से किया जा सकता है रुचि है। यह गाइड-लाइन मनमानेपन के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा है। सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग। इस नियम का उद्देश्य है - मृत लकड़ी को काट लें। दूसरी ओर पेंशन नियमों का नियम 2 (2) हाथ 'कोई मार्गदर्शक रेखा प्रदान नहीं करता है और पूर्ण विवेकाधिकार देता है सरकार। नियम के तहत 'पब्लिक' में कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्याज' [799 ई-एफ)"।

(3). यद्यपि नियम पारस्परिक रूप से अनन्य हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए बनाया गया लेकिन दोनों का परिचालन प्रभाव योग्यता सेवा के 30 वर्ष पूरे

किए, किसी भी समय सेवानिवृत्त हो सकते हैं। पेंशन नियमों के नियम 2(2) के तहत सरकार का विवेकाधिकार। कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसने योग्यता के 30 वर्ष पूरे कर लिए हों। सेवा में हैं और 55 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं किया है, इसके लिए उठाया जा सकता है के तहत समयपूर्व सेवानिवृत्ति। नियम 2 (2)। चूँकि कोई सुरक्षित-रक्षक नहीं हैं नियम में प्रदत्त, विवेकाधिकार निरपेक्ष है और होने में सक्षम है मनमाने ढंग से और एक समान हाथ के साथ उपयोग किया जाता है। पेंशन का नियम 2 (2) इसलिए नियम भारत संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। [799 जी, 800 बी-सी]

(4) एक वैधानिक नियम को कार्यपालिका द्वारा संशोधित या संशोधित नहीं किया जा सकता है। निर्देश दिए। एक वैध नियम जिसमें कुछ कमी या अंतराल हो, वह उपयुक्त हो सकता है। कार्यकारी निर्देशों द्वारा निर्धारित, लेकिन एक वैधानिक नियम जो है। कार्यपालिका के समर्थन से संवैधानिक रूप से अमान्य को मान्य नहीं किया जा सकता है। निर्देश दिए। निर्देश केवल पूरक हो सकते हैं और प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं नियम। [800 ई]

(5) गृह मंत्रालय, दिनांकित ज्ञापन 30 नवंबर, 1962 को संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत जारी नहीं किया गया है। भारत का प्रावधान और इस तरह से वैधानिक नहीं हो सकता है। ज्ञापन है भारत अध्यक्ष के नाम पर जारी किए गए कार्यकारी निर्देशों की प्रकृति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 (1) के तहत आवश्यक। [801 डी]

भारत संघ व अन्य बनाम वी.आर. नरसिम्हन, ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 1733, प्रतिष्ठित।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1361/1974।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 1972 की विशेष अपील संख्या 60 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 21.11.1973 से।

अनिल देव सिंह, सी.वी.एस. राव और तारा चंद शर्मा याचिकाकर्ता की ओर से।

प्रत्यर्थी के लिए आर.डी. उपाध्याय।

न्यायालय का निर्णय कुलदिप सिंह, जे. द्वारा दिया गया था

विचार के लिए छोटा प्रश्न क्या उदारीकृत पेंशन नियम, 1950 (जिसे इसके बाद 'पेंशन नियम' कहा जाता है) का नियम 2 (2), जो केंद्र सरकार को किसी सरकारी कर्मचारी को 30 साल की योग्यता सेवा पूरी करने के बाद उसे तीन महीने का नोटिस देकर या इस तरह के नोटिस के बदले में भुगतान करके किसी भी समय सेवानिवृत्त करने की अनुमति देता है, सरकार को दिशाहीन शक्तियां प्रदान करता है और इस तरह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

इजहार हुसैन डाक और टेलीग्राफ विभाग में शामिल हुए। 4 जून, 1935 को क्लर्क। निदेशक, डाक सेवा ने 21 अप्रैल, 1970 के एक आदेश द्वारा उन्हें पेंशन नियमों के नियम 2 (2) के तहत सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया। इजहार हुसैन ने सेवानिवृत्ति के आदेश को एक तरीके से चुनौती दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पेंशन नियमों के नियम 2 (2) में कोई कमजोरी नहीं है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष इजहार हुसैन द्वारा दायर विशेष अपील को स्वीकार कर लिया गया और पेंशन नियमों के नियम 2 (2) को अमान्य घोषित कर दिया गया और इजहार हुसैन के सेवानिवृत्त आदेश को खारिज कर दिया गया। भारत संघ उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा अपील में आया है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। मौलिक नियमों के नियम 56 (जे) के तहत सरकार को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद जनहित में किसी कर्मचारी को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है। सरकार के पास पेंशन नियमों के नियम 2(2) के तहत किसी भी समय किसी कर्मचारी को

सेवानिवृत्त करने की शक्ति भी है। योग्यता सेवा के 30 वर्ष पूरे करने के बाद। हम इन नियमों को उद्धृत कर सकते हैंः

> “एफ.आर. 56 (जे) इसमें कुछ भी निहित होने के बावजूद नियम, उपयुक्त प्राधिकारी, यदि उसकी राय है कि ऐसा करना लोक हित में है, पूर्ण है। किसी भी सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद उसका अधिकार उसे सूचना देकर पचास-पाँच वर्ष की आयु प्राप्त की लिखित में तीन महीने से कम नहीं।

बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी लागू नहीं होगा खंड (ङ) या खंड (च) में निर्दिष्ट सरकारी कर्मचारी।

> "नियम 2 (2) एक अधिकारी किसी भी समय सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है। 30 साल की योग्यता सेवा पूरी करने के बाद बशर्ते कि वह इस संबंध में लिखित सूचना देगा। तिथि से कम से कम 3 महीने पहले उपयुक्त प्राधिकारी जिसे वह सेवानिवृत्त करना चाहता है। सरकार को भी आवश्यकता हो सकती है। 30 वर्ष पूरा करने के बाद किसी भी समय सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी योग्यता सेवा प्रदान की गई है कि उपयुक्त प्राधिकारी इस संबंध में अधिकारी को लिखित रूप में एक सूचना देगा। उस तारीख से कम से कम तीन महीने पहले जिस दिन उसे करना आवश्यक है। सेवानिवृत्त, या ऐसे के बदले में तीन महीने का वेतन और भत्ते नोटिस करें"।

मौलिक नियम 56 (जे) को पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए सरकार का प्रावधान है कि इस तरह की शक्ति का उपयोग केवल सार्वजनिक हित में किया जा सकता है। यह गाइड लाइन सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने प्रयोग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा है। इस नियम का उद्देश्य मृत लकड़ी को काटना है। दूसरी ओर सरकार पेंशन नियमों के नियम

2 (2) में कोई मार्गदर्शक रेखा नहीं दी गई है और इसमें पूर्ण विवेकाधिकार दिया गया है। नियम के तहत 'जनहित' में कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु में सरकारी सेवा में शामिल होता है, वह 51/52 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो सकता है क्योंकि तब तक उसने 30 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी कर ली होगी। हालांकि नियम पारस्परिक रूप से अनन्य हैं और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन दोनों नियमों का परिचालन प्रभाव यह है कि एक सरकारी कर्मचारी जो 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, उसे केवल 'जनहित' के आधार पर एफ.आर. 56 (जे) के तहत समय से पहले सेवानिवृत्त किया जा सकता है, जबकि एक अन्य सरकारी कर्मचारी जो केवल 51 वर्ष का है और जिसने 30 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी कर ली है, उसे पेंशन नियमों के नियम 2 (2) के तहत सरकार के विवेक पर किसी भी समय सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

पेंशन नियमों के नियम 2 (2) का उद्देश्य खरपतवार [1989] 3 एस. सी. आर. भी हो सकता है। उन सरकारी कर्मचारियों को बाहर कर दिया जिन्होंने अपनी उपयोगिता को पूरा किया है लेकिन इस आशय की कोई मार्गदर्शिका नियम में नहीं दी गई है। नियम सरकार को सेवानिवृत्त करने के लिए दिशाहीन विवेकाधिकार देता है। 30 साल की योग्यता सेवा पूरी करने के बाद किसी भी समय नौकर हालाँकि उसे सेवानिवृत्ति की आयु तक बने रहने का अधिकार है जो वे 58 वर्ष के हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसने 30 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी कर ली है और 55 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, उसे नियम के तहत समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए उठाया जा सकता है। चूँकि नियम में कोई सुरक्षा गार्ड प्रदान नहीं किए गए हैं, इसलिए विवेकाधिकार पूर्ण है और है। मनमाने ढंग से और एक समान हाथ से उपयोग करने में सक्षम। हम, इससे पहले, उच्च न्यायालय की खंड पीठ से सहमत हैं और मानते हैं कि पेंशन नियमों का नियम 2 (2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

श्री अनिल देव सिंह, भारत संघ की ओर से पेश होते हुए यह माना गया कि भारत सरकार ने 11 जुलाई, 1955 और 8 फरवरी, 1956 को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि पेंशन नियमों के नियम 2 (2) के तहत तब प्रभावी होना चाहिए जब सार्वजनिक हित में ऐसी सेवानिवृत्ति आवश्यक हो। उनके अनुसार, नियम के पूरक होने के कारण, सेवानिवृत्ति का आदेश 'जनहित' में होना चाहिए और इस प्रकार नियम में मनमानेपन का कोई दोष नहीं है। हम विद्वान वकील के इस तर्क से सहमत नहीं हैं। एक वैधानिक नियम को कार्यकारी अनुदेशों द्वारा संशोधित या संशोधित नहीं किया जा सकता है। कुछ खामियों या अंतराल वाले एक वैध नियम को कार्यकारी निर्देशों द्वारा पूरक किया जा सकता है, लेकिन एक वैधानिक नियम जो संवैधानिक रूप से अमान्य है, उसे कार्यकारी निर्देशों के समर्थन से मान्य नहीं किया जा सकता है। निर्देश केवल पूरक हो सकते हैं और नियम को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं।

श्री अनिल देव सिंह ने तब गृह मंत्रालय पर निर्भरता रखी। 30 नवंबर, 1962 का कार्य ज्ञापन और तर्क दिया कि यह भारत के राष्ट्रपति के नाम पर जारी किया गया है और यह पेंशन नियमों के नियम 2 (2) में संशोधन का प्रभाव है। उनके अनुसार दोनों को एक साथ पढ़ने पर पेंशन नियमों के नियम 2 (2) के तहत शक्ति का उपयोग केवल खरपतवार हटाने के लिए किया जा सकता है - जो अनुपयुक्त कर्मचारी है। ज्ञापन का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

> "निर्देश दें कि केंद्रीय की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष सरकारी कर्मचारियों की होनी चाहिए। निम्नलिखित अपवादः
>
> 6. पूर्वगामी एस. आर. में कुछ भी निहित होने के बावजूद। पैराग्राफ, नियुक्ति प्राधिकारी को तीन महीने के नोटिस पर 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद एक सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने की आवश्यकता हो सकती है। यह उदारीकृत पेंशन नियम 1950 के नियम

2 (2) में पहले से ही निहित प्रावधानों के अतिरिक्त होगा, जो 30 साल की योग्यता सेवा पूरी करने वाले अधिकारी को सेवानिवृत्त करने के लिए होगा, और आमतौर पर 55 साल की आयु प्राप्त करने के बाद अनुपयुक्त कर्मचारियों को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी भी, 55 वर्ष की आयु के बाद, नियुक्ति प्राधिकारी को तीन महीने का नोटिस देने के बाद स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकता है।

7. ये प्रावधान पहली तारीख से प्रभावी होंगे। दिसंबर, 1962।"

ज्ञापन को नंगे पढ़ने से पता चलता है कि श्री सिंह के तर्क में एक घोर भ्रांति है। यह ज्ञापन भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत जारी नहीं किया गया है और इसलिए यह वैधानिक नहीं हो सकता है। यह ज्ञापन भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 (1) के तहत भारत के राष्ट्रपति के नाम पर जारी किए गए कार्यकारी निर्देशों की प्रकृति का है। यह मौलिक (छठा संशोधन) नियम, 1965 के पूर्वानुमति में जारी किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नियम 56 (जे) को मौलिक नियमों में शामिल किया गया था। अन्यथा भी ज्ञापन के पैरा 6 में पेंशन नियमों के नियम 2 (2) में कुछ भी नहीं जोड़ा जा सका और न ही जोड़ा गया। पेंशन नियमों के नियम 2 (2) का उल्लेख यह स्पष्ट करने के लिए किया गया था कि पैरा 6 के तहत सेवानिवृत्त होने की शक्ति पेंशन नियमों में पहले से निहित शक्ति के अतिरिक्त थी। "अनुपयुक्त कर्मचारियों को निकाल देना" शब्दों को केवल पैरा 6 के तहत सेवानिवृत्त होने की शक्ति के रूप में पढ़ा जा सकता है, न कि पेंशन नियमों के नियम 2 (2) के तहत। इस प्रकार तर्क में कोई बल नहीं है और हम इसे अस्वीकार करते हैं।

भारत संघ और अन्य मामलों में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए वी.आर. नरसिम्हन, ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 1733 श्री अनिल देव सिंह ने तर्क दिया। इस

न्यायालय ने कहा कि रेलवे पेंशन नियमावली के पैरा 620, जो पेंशन नियमों के नियम 2 (2) के समान है, को बरकरार रखा गया है। नरसिम्हन के मामले में भारतीय रेलवे के नियम 2046 का दायरा इस न्यायालय द्वारा रेलवे पेंशन नियमावली की स्थापना संहिता और पैरा 620 पर विचार किया गया था। नियम 2046 एक सांविधिक नियम है और मौलिक नियम 56 (जे) के समान है। पैरा 620 कार्यकारी निर्देशों की प्रकृति का है लेकिन इसी तरह पेंशन नियमों के नियम 2 (2) के रूप में लिखा गया है। मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि नियम 2046 को संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाया गया है और एक व्यापक नियम होने के नाते, रेलवे कर्मचारी केवल सरकारी कर्मचारी हैं। उक्त नियम और पैरा 620 द्वारा लागू किया जाना अमान्य और निष्क्रिय था। यह न्यायालय उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गयाः

"इस प्रकार रेलवे के पैरा 620 के संचालन के क्षेत्र पेंशन नियमावली खंड (एच) और (के) से अलग है। नियमों के नियम 2046 का। रेलवे पेंशन का पैरा 620 नियमावली को नियम 2046 के पूरक के रूप में माना जाना चाहिए। नियम हैं। उक्त पैरा जो इसके द्वारा तैयार किया गया है। केंद्र सरकार अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत देय दिया जाना चाहिए। प्रभाव क्योंकि कोई वैधानिक प्रावधान या नियम नहीं बनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत जो यह इसके साथ असंगत है"।

इस प्रकार नरसिम्हन के मामले की विवाद से कोई प्रासंगिकता नहीं है। इस मामले में शामिल। मैनुअल के किसी भी नियम या पैरा 620 को इस आधार पर कोई चुनौती नहीं दी गई थी कि यह रेलवे अधिकारियों को रेलवे कर्मचारियों को चुनने और चुनने की दिशाहीन शक्ति देता है। पूर्व-परिपक्व सेवानिवृत्ति का उद्देश्य। नियमावली के पैरा 620 में वैधानिक नियम 2046 का पूरक होने के कारण पेंशन नियम के नियम 2 (2) के साथ कोई समानता नहीं है जो एक वैधानिक नियम है। किसी भी मामले में

वर्तमान मामले में हमारे सामने जो मुद्दा था, वह न तो नरसिम्हन के मामले में शामिल था और न ही उठाया गया था और इस तरह श्री अनिल देव सिंह उक्त फैसले से कोई समर्थन प्राप्त नहीं कर सकते।

इस प्रकार इसमें हस्तक्षेप करने के लिए कोई कानूनी या न्यायसंगत आधार नहीं है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय। अपील को लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है जिसे हम 3,000 रुपये के रूप में निर्धारित करते हैं।

आर.एस. याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।